



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 52-2018/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 28, 2018 (CHAITRA 7, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 मार्च, 2018

संख्या 35/आ0-1/पं0अ01/1914/धा0 59/2018.—पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1), की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 67/आ0-1/पं0अ01/1914/धा0 9/2017, दिनांक 4 अगस्त, 2017 के प्रतिनिर्देश से, मैं, आशिमा बराड़, आबकारी आयुक्त, हरियाणा वित्तायुक्त की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा, हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति नियम, 1970, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हूँ, अर्थात्:—

- (1) ये नियम हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति (संशोधन) नियम, 2018, कहे जा सकते हैं।  
(2) ये प्रथम अप्रैल, 2018, से लागू होंगे।
- हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति नियम, 1970 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 24 में,—  
(i) खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(i) प्ररूप अनु0—। में अनुज्ञप्ति के लिए,—

- |   |                |
|---|----------------|
| (क) राजस्व जिला गुरुग्राम तथा फरीदाबाद के लिए               | ₹ 1,60,00,000  |
| (ख) गुरुग्राम तथा फरीदाबाद के सिवाए राज्य में सभी अन्य जिले | ₹ 1,30,00,000” |

परन्तु ऐसी कोई भी अनुज्ञप्ति तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक 30.00 लाख रुपये की प्रतिदेय प्रतिभूति जमा नहीं की जाती है, जो अधिनियम के अधीन जब्त किए जाने अथवा देय किसी राशि या शास्ति के लिए समायोजित किये जाने के लिए दायी होगी।”;

- (ii) खण्ड (i—ख ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(i—ख ख ) प्ररूप अनु0—4/अनु0—5 में अनुज्ञप्तियों के लिए:—

- |   |             |
|---|-------------|
| (क) अनु0—4/अनु—5 अनुज्ञप्ति 5 स्टार<br>ग्रेडिंग तथा से अधिक के होटलों को<br>दी जाएगी: | ₹ 40,00,000 |
|---|-------------|

परन्तु अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्तिधारी उभरते आवासीय नगर क्षेत्रों तथा ऐसे स्थानों में भी प्रदान की जाएगी, जहां हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम ने औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र तथा थीम/विशिष्ट पार्क विकसित किए हैं जैसे कि औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र, मानेसर, औद्योगिक आदर्श नगर-क्षेत्र, बावल, औद्योगिक आदर्श नगर-क्षेत्र, रोहतक, औद्योगिक नगर पार्क मानेसर, टेक्नोलोजी पार्क, पंचकूला :

परन्तु यह और कि ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को किसी और फीस के बिना, कक्ष सर्विस (अनु0-3) सहित एक मुख्य बार तथा तीन अतिरिक्त बिन्दु अनुज्ञात किए जाएंगे। ऐसी अनुज्ञप्तियां आगे रात-दिन के एक मुख्य बार को संचालित करने के लिए अनुज्ञात की जाएगी। अनु0-3 अनुज्ञप्ति रखने वाले के आधार पर, ये होटल अन्य खाद्य वस्तुओं तथा पेयों के साथ-साथ होटल कक्षों में रखे रेफरीजरेटरों में मदिरा रखने के लिए अनुमत है। अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्तिधारी बार 12.00 (मध्यरात्रि) बजे तक खुले रखे जा सकते हैं। बारों का समय दस लाख रुपये की अतिरिक्त वार्षिक फीस के भुगतान पर एक घन्टे तक बढ़ाया जा सकता है। मदिरा का विक्रय, जिसमें अनु04/अनु0-5 बाजार (बार) के माध्यम से निर्मित आयातित विदेशी मदिरा भी शामिल है, 18 प्रतिशत की दर से वैट + वैट पर 5 प्रतिशत की दर से अधिशुल्क आकर्षित करेगा।

(ख) 4 स्टार की ग्रेडिंग वाले होटल

₹ 33,00,000 :

परन्तु ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को किसी और फीस के बिना, कक्ष सर्विस (अनु0-3) सहित, एक मुख्य बार तथा दो अतिरिक्त बिन्दु अनुज्ञात किए जाएंगे। ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को आगे रात-दिन के एक मुख्य बार को संचालित करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। अनु0-3 अनुज्ञप्ति रखने वाले के आधार पर, ये होटल अन्य खाद्य वस्तुओं तथा पेयों के साथ-साथ होटल कक्षों में रखे रेफरीजरेटरों में मदिरा रखने के लिए अनुमत हैं:

परन्तु यह और कि राज्य में कहीं भी स्थित होटल को भी अस्थायी तौर पर एल-4/एल-5 अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी जो प्रार्थी अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने वाले वित्तीय वर्ष के अन्दर पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार से 4 सितारा तथा इससे उपर का वर्गीकरण प्रस्तुत करेगा तथा असफल होने की स्थिति में अस्थायी अनुज्ञप्ति का बाद में नवीकरण नहीं किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी एल-4/एल-5 अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के एक मास के भीतर स्टार रेटिंग के लिए आवेदन करेगा।

(ग) 3 स्टार की ग्रेडिंग वाले होटल

₹ 18,00,000:

परन्तु ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को किसी और फीस के बिना, एक अतिरिक्त बिन्दु तथा कक्ष सर्विस (अनु0-3) सहित, एक मुख्य बार अनुज्ञात किया जाएगा। अनु0-3 अनुज्ञप्ति वाले के आधार पर, ये होटल अन्य खाद्य वस्तुओं तथा पेयों के साथ-साथ होटल कक्षों में रखे रेफरीजरेटरों में मदिरा रखने के लिए अनुमत हैं:

परन्तु यह और कि उपरोक्त वर्णित प्रवर्ग (क), (ख) तथा (ग) के ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को अपनी वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के 50 प्रतिशत के बराबर एक बार फीस (वन टाइम फीस) के भुगतान पर बैंकट हाल तथा मुख्य बार से भूमिगत लान, स्रोत सहित अपने परिलक्षित (पहचानित) तथा अनुमोदित हालों के तीन (03) तक में किए गए कार्यों, पार्टियों, आयोजनों तथा बैठकों में मदिरा परोसने के लिए भी अनुज्ञात किया जाएगा।

अनु0-4/अनु0-5 तथा अनु0-12 ग अनुज्ञप्तिधारियों को सम्बन्धित जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) की अनुमति से केवल राज्य के बाहर से सीमाशुल्क-बन्धपत्र भाण्डागारण से सीधे रुप से आयातित विदेशी मदिरा (बीआईओ) प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जो एक सप्ताह में ऐसे अनुरोध का निपटान सुनिश्चित करेंगे। बार अनुज्ञप्तिधारी राज्य में अनु0-1 ख च से आयातित विदेशी मदिरा (बीआईओ) की अपनी आपूर्ति लेने के लिए भी अनुमत हैं। इसके अतिरिक्त, अनु0-1 ख च से भिन्न किसी अन्य स्रोत से आयातित विदेशी मदिरा (बीआईओ) प्राप्त करने वाले बार अनुज्ञप्तिधारी स्कोच, विस्की, रम, वोदका, जिन तथा ब्राण्डी के दशा में ₹ 60.00 प्रति प्रूफ लीटर की दर से परमिट फीस तथा बाईन लिक्युअर, बीयर और साईडर की दशा में ₹ 20/- प्रति बल्क लीटर की परमिट फीस का भुगतान करेगा। परमिट फीस के अतिरिक्त, निर्धारण फीस भारत में बनी विदेशी मदिरा (बीआईओ) पर उद्गृहीत की जाएगी जब राज्य के बाहर से सीधे रुप से आयातित की गई है। निर्धारण फीस बीयर, वाईन, लिक्युअर तथा साईडर पर ₹ 300.00 प्रति बल्क लीटर तथा स्कोच, बिस्की, रम, वोदका, जिन, ब्राण्डी इत्यादि पर ₹ 1200/- प्रति प्रूफ लीटर की दर से बार अनुज्ञप्तिधारियों के हाथों से उद्गृहीत की जाएगी:

परन्तु ₹ 5.00 लाख की प्रतिदेय प्रतिभूति अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्तिधारियों से ली जाएगी।”;

(घ) प्ररूप अनु04/अनु0-5 में अनुज्ञप्ति के लिए, खण्ड (घ) तथा (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(घ) हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा संचालित बार (बारों) के लिए

₹ 2,00,00,000 की प्रशमन फीस

(ङ) हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा उनके जिमखाना तथा गोल्फ क्लबों में संचालित बार

₹ 1,00,00,000 की प्रशमन फीस:

परन्तु ₹ 6.00 लाख की कम्पोजिट प्रतिभूति हरियाणा पर्यटन विभाग तथा हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण से कम्पोजिट अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त ली जाएगी।”;

- (iii) (क) खण्ड (ii) में, "₹50,00,000" अंकों तथा चिह्नों के स्थान पर, "₹60,00,000" अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (ख) खण्ड (ii-क) "₹40,00,000" अंकों तथा चिह्नों के स्थान पर, "₹50,00,000" अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (ग) खण्ड (ii-ख) "₹75,00,000" अंकों तथा चिह्नों के स्थान पर, "₹80,00,000" अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।";
- (घ) विद्यमान खण्ड (ii-ख) में, "विशेषाधिकार फीस" शीर्ष तथा उसके नीचे प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष तथा उसके नीचे प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"विशेषाधिकार फीस

भारत में बनी विदेशी स्पिरिट

₹20.00 प्रति पूफ लीटर

बीयर

₹14.00 प्रति बल्क लीटर";

- (iv) खण्ड (ii-ख) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु हरियाणा राज्य में बाटलिंग प्लांट की स्थापना करने के लिए आवेदक से आशय पत्र प्राप्त किया जाएगा। आशय पत्र एक वर्ष की वैध अवधि सहित कतिपय निबन्धनों तथा शर्तों सहित जारी किया जाएगा। यह सरकार की अनुमति से जारी किया जाएगा तथा प्रथम बार के लिए आशय पत्र प्रदान करने के लिए प्रति वर्ष फीस तीस लाख रुपये होगी। एक वर्ष के प्रथम विस्तार के लिए आशय पत्र की पुनः वैधीकरण के लिए फीस आशय पत्र देने के लिए फीस की दर समान होगी तथा एक वर्ष के प्रत्येक पश्चात्तवर्ती विस्तार के लिए पुनः वैधीकरण फीस पूर्व वर्ष की फीस का 125 प्रतिशत होगी।

आशय पत्र के पुनः वैधीकरण के लिए फीस जहां पहले आशय पत्र या इसके पुनः वैधीकरण के लिए कोई भी फीस प्रभारित नहीं की गई थी वहां तीस लाख रुपये तथा पश्चात्तवर्ती पुनः वैधीकरण पूर्व वर्ष की फीस के 125 प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी।";

- (v) खण्ड (ii-ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ii-ग) आई एम एफ एस पर बाटलिंग फीस निम्न अनुसार उदगृहीत की जाएगी:-

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| (क) उनके अपने ब्राण्ड की बाटलिंग डी-2 अनुज्ञप्ति के लिए  | ₹11.00/- प्रति पूफ लीटर  |
| (ख) उनके अपने ब्राण्ड की बाटलिंग प्लांट बाटलिंग के लिए   | ₹18.00/- प्रति पूफ लीटर  |
| (ग) उपरोक्त (क) तथा (ख) में न आने वाले ब्राण्ड की बाटलिंग के लिए तथा जहाँ फ्रेन्चाईज फीस उदगृहीत नहीं होती | ₹20.00/- प्रति पूफ लीटर  |
| (घ) ब्रुअरज के द्वारा बीयर के बाटलिंग के लिए   | ₹6.00/- प्रति बल्क लीटर: |

परन्तु बाटलिंग फीस, निर्यात के लिए मदिरा के साथ साथ स्थानीय उपभोग के लिए भी मदिरा पर उदगृणीय होगी, यदि कोई भी विशेषाधिकार (फ्रेन्चाईज) फीस उदगृहीत नहीं की गई है।";

- (vi) खण्ड (iv) में, अन्त में विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु प्ररूप अनु0-12 क में अनुज्ञप्ति ₹500 प्रतिदिन समारोह के भुगतान पर एक दिन के लिए कब्जा सीमा से बाहर प्राईवेट स्थान पर व्यक्तिगत के लिए उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा दी जा सकती है।

वाणिज्यिक स्थानों जैसे कि समारोह आयोजित करने, एकत्र होने के लिए बैंकट हाल, फार्म हाउस, सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशालाओं को ₹50,000 प्रतिवर्ष की रजिस्ट्रेशन फीस के भुगतान पर जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के पास रजिस्टर्ड कराना होगा। ऐसे मामलों में फीस ढांचा निम्न अनुसार होगा:-

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| (क) आबकारी विभाग से रजिस्टर्ड वाणिज्यिक स्थानों पर मदिरा परोसने वाले व्यक्तियों के लिए | ₹ 5,000 प्रतिदिन प्रति समारोह |
|--|-------------------------------|

- (ख) वाणिज्यिक स्थानों पर मदिरा परोसने वाले व्यक्तियों के लिए जो आबकारी विभाग के पास रजिस्टर्ड नहीं है। ₹10,000 प्रतिदिन प्रति समारोह

वाणिज्यिक स्थान, जो विभाग से रजिस्टर्ड नहीं है, को प्रतिमास पाँच से अधिक अनुज्ञप्तियों जारी नहीं की जाएगी। सभी वाणिज्यिक स्थानों में अनु0-12 क अनुज्ञप्ति को देने के लिए आवेदन में प्रबन्धक के ब्योरे अर्थात् नाम तथा शैली, जी.एस.टिन इत्यादि तथा मेहमानों की लगभग संख्या वर्णित होगी।”;

- (vii) खण्ड (iv-ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(iv-ख) प्ररूप अनु0-12ग में अनुज्ञप्ति के लिए,-

- |  |                |
|--|----------------|
| (क) राजस्व जिला गुरुग्राम के लिए                           | ₹ 15,00,000 /- |
| (ख) जिला फरीदाबाद के लिए                                   | ₹ 12,00,000 /- |
| (ग) गुरुग्राम तथा फरीदाबाद के सिवाए राज्य के सभी अन्य जिले | ₹ 9,00,000 /-: |

परन्तु इस उद्देश्य के लिए गठित जिला स्तर समिति द्वारा विहित मानदंडों और शर्तों को पूरा करने के लिए जरूरी अवसंरचना तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, इसके अलावा जिला मुख्यालयों के शहरों में स्थित प्रतिष्ठित क्लबों को एल-12सी अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएंगे:

परन्तु यह और कि जिला मुख्यालय के शहरों में आवासीय कॉलोमिनियम के लिए एल-12ग के रूप में अनुज्ञप्ति की अनुमति प्रदान की जाएगी। मुख्य बार एल-4/एल-5 अनुज्ञप्ति के बराबर होगा, जब कॉलोमिनियम के अन्दर कोई अतिरिक्त मिनी क्लब प्रत्येक ऐसे अतिरिक्त मिनी क्लब के लिए अपने मुख्य बार के अनुज्ञप्ति फीस के 20 प्रतिशत की दर से अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा। यह इस शर्त के अधीन होगा कि केवल कोलोमिनियम या उसके निवासियों के मेहमानों को इस सुविधा का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी:

परन्तु यह और कि एल-12 सी अनुज्ञप्ति सरहिन्द क्लब, अम्बाला को प्रदान किए जाने पर, सेना के अधिकारी को सी.एस.डी. कैटीन के माध्यम से अपने कोटा का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी जबकि नागरिक सदस्य सी.एस.डी. कैटीन के माध्यम से सप्लाई की जाने वाली शराब के लिए हकदार नहीं होंगे:

परन्तु यह और कि ₹5.00 लाख की प्रतिदेय प्रतिभूति अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त अनु0-12ग अनुज्ञप्तिधारियों से ली जाएगी।”;

- (viii) खण्ड (iv-ग) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

(iv-ग) प्ररूप अनु0-12 ग ग में अनुज्ञप्ति के लिए,-

- |   |            |
|---|------------|
| (क) 9 होल तक क्षमता सहित गोल्फ क्लब (दो विक्रय बिन्दुओं सहित)   | ₹40,00,000 |
| (ख) 18 होल तक क्षमता सहित गोल्फ क्लब (तीन विक्रय बिन्दुओं सहित) | ₹50,00,000 |

परन्तु शराब परोसने के लिए अनुज्ञप्ति केवल 9 होल या उससे अधिक सुविधाओं वाले गोल्फ क्लबों को प्रदान की जाएगी तथा उन्हें किसी भी होटल या किसी भी प्रकार के बार अनुज्ञप्ति के साथ अतिरिक्त स्थल चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अनु0-12 गग क्लब बार के अनुज्ञप्तिधारी 12.00 (मध्य रात्रि) बजे तक खुले रख सकते हैं। बारों का समय दस लाख रुपये की अतिरिक्त वार्षिक फीस के भुगतान पर एक घण्टे तक बढ़ाया जा सकता है।

**टिप्पण 1.-** पहले से ही अनुज्ञात उपरोक्त दिए गए स्थल के अलावा प्रत्येक ऐसे स्थल के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस की 20 प्रतिशत फीस के समान अदायगी पर चलाने की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा प्रति अनुज्ञप्ति अधिकतम तीन अतिरिक्त स्थल चलाने की अनुमति दी जायेगी।

**टिप्पण 2.-** हरियाणा पर्यटन तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा उनके अपने जिमखाना तथा गोल्फ क्लबों में बार चलाने की दशा में, उन्हें ऐसे प्रत्येक स्थल के लिए एक लाख रुपये की अतिरिक्त फीस पर चलाने की अनुमति दी जाएगी:

परन्तु ₹5.00 लाख की प्रतिदेय प्रतिभूति अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त अनु0-12 गग कल्ब बार अनुज्ञप्तिधारियों से ली जाएगी।”;

- (ix) खण्ड (v) में, खण्ड (i) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

“(v) (i) देसी मदिरा (अनु0-13) के थोक बाजार के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस जिले में ₹30.00 लाख रुपये प्रति बाजार होगी। अनुज्ञप्तिधारी से जिले में ₹10.00 लाख प्रति अनु0-13 की प्रतिदेय प्रतिभूति राशि जमा करानी अपेक्षित होगी।”;

- (x) खण्ड (i-ग) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

“(i-ग) प्ररूप अनु0-1 क ख में अनुज्ञप्ति के लिए ₹55,00,000;”;

- (xi) खण्ड (i-गग) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

“(i-गग) प्ररूप अनु0-1 क ख-1 में अनुज्ञप्ति के लिए ₹30,00,000;”;

- (xii) खण्ड (i-ड) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

“(i-ड) प्ररूप अनु0-1 ख में अनुज्ञप्ति के लिए ₹35,00,000;”;

- (xiii) खण्ड (i-डड.) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

“(i-डड) (क) ब्रुअर को प्ररूप अनु0-1ख1 में अनुज्ञप्ति के लिए ₹35,00,000;”

(ख) वाईन निर्माता को प्ररूप अनु0-1ख1 में अनुज्ञप्ति के लिए ₹25,00,000;”;

- (xiv) खण्ड (i-डडड) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

“(i-डडड) प्ररूप अनु0-1ख1-क में अनुज्ञप्ति के लिए ₹45,00,000;”;  
(पीने के लिए तैयार पेय)

- (xv) खण्ड (i-डडडड) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(i-डडडड) प्ररूप अनु0-1खच में अनुज्ञप्ति के लिए,-

(क) रिजर्व कीमत ₹62,50,00,000/- होगी;

(ख) उच्चतम बोली दाता को ई. निविदा के माध्यम से प्ररूप अनु0-1खच में अनुज्ञप्ति आबंटित किया जायेगा;

(ग) राज्य में केवल एक ही अनु0-1खच लाईसेंस होगा;

(घ) अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारी को राज्य में कहीं भी मुख्य आउटलेट के अतिरिक्त तीन आउटलेट/शाखाएं खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए प्रत्येक आउटलेट/शाखा पर अनु0-1खच की अनुज्ञप्ति फीस के 2 प्रतिशत के हिसाब से निर्धारित फीस लगाई जाएगी।

(ङ) यदि अकेले अनु0-1खच अनुज्ञप्ति के लिए रिजर्व कीमत के समान या उससे अधिक कोई भी पात्र निविदा प्राप्त नहीं होती है, तो उसे सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार निबंधनों तथा शर्तों पर पूर्ण रूप से सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन संस्था को आबंटित किया जायेगा। अनु0-1खच अनुज्ञप्ति के द्वारा मदिरा का स्टॉक उपलब्ध करवाने के लिए निम्नलिखित परमिट फीस तथा ब्रांड लेबल फीस उद्गृहीत की जाएगी

परमिट फीस

(क) स्कोच, विस्की, रम, वोदका, जिन, ब्राण्डी इत्यादि ₹ 75/- प्रति प्रूफ लीटर

(ख) वाईन, लिक्वर, बीयर तथा साईडर ₹ 30/- प्रति बल्क लीटर

## ब्राण्ड लेबल फीस

(क) स्कोच/विस्की	₹ 70,000 प्रति ब्रांड
(ख) बीयर	₹ 60,000 प्रति ब्रांड
(ग) रम/वोदका/वाईन	₹ 35,000 प्रति ब्रांड
(घ) जिन/ब्राण्डी साईडर/चैम्पेजन/लिकअर	₹ 25,000 प्रति ब्रांड”;

(xvi) खण्ड (i-छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(i-छ) प्ररूप अनु0-1-ग में अनुज्ञप्ति के लिए	प्रत्येक के सामने नीचे दी गई दरों पर वार्षिक फीस
(i) विस्की/स्कोच	₹ 95,000 प्रति ब्राण्ड
(ii) बीयर	₹ 75,000 प्रति ब्राण्ड
(iii) रम	₹ 55,000 प्रति ब्राण्ड
(iv) जिन/वोदका	₹ 40,000 प्रति ब्राण्ड
(v) वाईन/ब्राण्डी/साईडर/चैम्पेजन	₹ 25,000 प्रति ब्राण्ड
(vi) सीएसडी की आपूर्ति के लिए वोदका/ब्राण्डी/साईडर/वाईन तथा चैम्पेजन	₹ 10,000 प्रति ब्राण्ड
(vii) देसी मदिरा	₹ 95,000 प्रति ब्राण्ड
(viii) पीने के लिए तैयार पेय (आरटीबी)	₹ 85,000 प्रति ब्राण्ड
(ix) राज्य से बाहर निर्यात के लिए ब्रांड लेबल फीस (सभी प्रकार के ब्रांडों के लिए)	₹ 60,000 प्रति ब्राण्ड:

परन्तु बाटलिंग फीस, निर्यात के लिए मदिरा के साथ साथ स्थानीय उपभोग के लिए भी मदिरा पर उद्ग्रहणीय होगी, यदि कोई भी विशेषाधिकार (फ्रैन्चाईज) फीस उद्ग्रहीत नहीं की गई है।”

3. उक्त नियमों में, नियम 27-क में,-

(i) उप-नियम (1) में, खण्ड (iii) तथा (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

“(iii) (क) शापिंग माल में स्थित अनु0-2 अनुज्ञप्ति द्वारा प्राप्त प्ररूप अनु0-10ख में अनुज्ञप्ति के लिए फीस	₹ 10,00,000
(ख) शापिंग माल में डिपार्टमेंटल स्टोर में स्थित प्ररूप अनु0-10ख में अनुज्ञप्ति के लिए फीस	₹ 20,00,000
(iv) प्ररूप अनु0-10ग में अनुज्ञप्ति के लिए	₹ 12,00,000
(v) प्ररूप अनु0-10घ में अनुज्ञप्ति के लिए	₹ 8,00,000”।

4. उक्त नियमों में, नियम 31क में, “300” अंको के स्थान पर, “325” अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

5. उक्त नियमों में, नियम 36-क में,-

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(1) देसी मदिरा और भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के खुदरा बाजारों का आबंटन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ई-निविदा के माध्यम से ग्रुप जोनों में किया जाएगा। कमाण्ड क्षेत्र जोन आबकारी व्यवस्था में जोन के लिए भौगोलिक क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया जाएगा। जोन के लिए कमाण्ड क्षेत्र में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र दोनों शामिल होंगे। अनुज्ञप्तिधारी ठेका के किस्म अर्थात् केवल देसी मदिरा या केवल भारत में निर्मित विदेशी मदिरा या दोनों देसी मदिरा और भारत में बनी विदेशी मदिरा का निर्णय करने के लिए सुगमता होगी। कुल सीमा छह खुदरा ठेकों की होगी और जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के पूर्व अनुमोदन से जोन के कमाण्ड क्षेत्र में अपना ठेका किसी स्थल पर स्थापित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी देसी मदिरा/भारत में निर्मित विदेशी मदिरा, जैसी भी स्थिति हो, के लिए प्रत्येक व्यक्तिक ठेके हेतु भी अनुपातिक कोटे का निर्णय करेगा। आबंटन की प्रक्रिया सम्बन्धित जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी), उप आबकारी तथा कराधान

आयुक्त (बिक्री कर) सहित उपायुक्त इसके सदस्य के रूप में से मिलकर बनने वाली समिति भागीदारों की उपस्थिति में जो विभाग द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली ई-निविदाओं के मूल्यांकन की तिथि पर उपस्थित होने के इच्छुक हो द्वारा संचालित की जायेगी। ठेकों के जोन का आबंटन ई-निविदाएं आमन्त्रित करते हुए किया जाएगा। उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आ0) अपने जिले में स्थित सभी अनु0-2, अनु0-14क ठेकों, उप-ठेकों तथा अनुमत कक्ष की भौगोलिक सूचना प्रणाली निर्देशांक को अपलोड करेंगे:

परन्तु अनुज्ञप्ति के रद्दकरण की दशा में, पुनः आबंटन की प्रक्रिया तुरन्त विज्ञापन के माध्यम से ई-निविदाएं आमन्त्रित करते हुए प्रारम्भ की जायेगी। पुनः आबंटन के लिए आरक्षित मूल्य शेष अवधि, जिसके लिए ठेकों का जोन मूल अनुज्ञप्ति फीस का उपयोग करते हुए पुनः आबंटित किया जाना है, के लिए अनुपातिक रूप में संगणित किया जाएगा। यदि कोई भी ई-निविदा प्राप्त नहीं हुई तो आरक्षित मूल्य, उपर वर्णित मूल आरक्षित मूल्य का दस प्रतिशत या पचास लाख रुपये जो भी कम हो से घटाते हुए होगा और आमन्त्रित ई-निविदा की प्रक्रिया पुनः दोहराई जाएगी जब तक ठेकों के जोन का पुनः आबंटन नहीं हो जाता है। यह पुनः आबंटन मूल अनुज्ञप्तिधारी के जोखिम और लागत पर किया जाएगा।

(ii) उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(2) ई-बोली के आमन्त्रण के बारे में विस्तृत प्रक्रिया को आबकारी तथा कराधान आयुक्त (वित्तायुक्त) द्वारा पूर्ण किया जाएगा जो कि विभाग की वेब साइट [www.haryanatax.gov.in](http://www.haryanatax.gov.in) पर परदर्शित की जाएगी। बोली में भागीदारी के लिए पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन करते समय आवेदक को आधार नम्बर जमा करना अनिवार्य होगा। किसी विधिक समस्या से बचने के लिए, यदि आबकारी तथा कराधान आयुक्त (वित्तायुक्त) का कोई भी निर्णय दस दिन की अनुबद्ध अवधि के भीतर सूचित नहीं किया जाता है, तो आबंटन आबकारी तथा कराधान आयुक्त (वित्तायुक्त) द्वारा अनुमोदित किया गया समझा जाएगा।

(iii) उप-नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(5) बोलीदाता को प्रत्येक जोन के लिए ₹75,000 की भागीदारी फीस जमा करानी होगी। भागीदारी फीस वापसी-योग्य नहीं है तथा समायोजनयोग्य नहीं है। भागीदारी फीस उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के पक्ष में या तो नकदी में या डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा सम्बन्धित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के कार्यालय में जमा की जाएगी।

(iv) उप-नियम (12) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(12) सभी सफल आबंटितियों को ठेकों/समूह ठेके का प्रचालन शुरू होने से पूर्व अपने जोन में एक शपथ पत्र तथा शोधन क्षमता प्रमाण-पत्र दायर करना अपेक्षित होगा। शपथ-पत्र विनिर्दिष्ट फार्मेट में 3 रुपये के मूल्य के नॉन-जुडीशियल स्टॉम्प पेपर पर होगा। इस शपथ-पत्र का आशय होगा कि वह किसी भी दण्ड न्यायालय द्वारा अजमानतीय अपराध अथवा पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) या अफीम अधिनियम, 1950 (1950 का 33), पूर्वी पंजाब अफीम धुम्रपान अधिनियम, 1948, पूर्वी पंजाब शीरा (नियंत्रण) अधिनियम 1948 (1948 का 11), भारतीय पॉवर एल्कोहल अधिनियम, 1948 (1948 का 22), जो कि हरियाणा में लागू है तथा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61), के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं किया गया है। शपथ-पत्र इस आशय का होगा कि व्यक्तिक्रमी नहीं है तथा उसने सभी पूर्व देयों या हरियाणा में आबकारी राजस्व का भुगतान कर दिया है। इसमें विहित शपथ-पत्र या शोधन क्षमता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की असफलता या मिथ्या-शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के लिए पर्याप्त आधार होगा, जो उसकी लागत तथा जोखिम पर पुनः आबंटित किया जाएगा:

परन्तु सभी सफल आबंटी ऐसे कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करवाएंगे जैसे कि मतदाता पहचान पत्र जिसमें पहचान पत्र का प्रमाण हो, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड इत्यादि तथा एम-75 के रूप में प्रतिभूति। सभी दस्तावेज नोटरी पब्लिक या राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित किए हुए हो तथा विधिवत उसके नाम तथा पद सहित छपी होनी चाहिए। दस्तावेज उसके व्यवसाय की शुरुआत से पहले प्रस्तुत किए जाएंगे। सफल आबंटिती अपने अन्य कागजातों के साथ आयकर विभाग के द्वारा जारी किए गए पैन कार्ड की कॉपी प्रस्तुत करेगा।

(v) उप-नियम (15) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(15) अनुज्ञप्तियां आबकारी तथा कराधान आयुक्त (वित्तायुक्त), हरियाणा के अनुमोदन के बाद कलक्टर की ओर से जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा दी जाएगी। लाइसेंस प्रदान करने से पूर्व उप आबकारी व कराधान आयुक्त(आबकारी) यह सुनिश्चित करेगा कि सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गए हैं।

- (vi) उप-नियम (17) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(17) अनुज्ञप्तिधारी जिसको देशी मदिरा (अनु0-14क) या भारत में बनी विदेशी मदिरा (अनु0-2) का खुदरा मदिरा बाजार आबंटित किया जाता है, तो राज्य में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्थित देशी मदिरा (अनु0-13) के अनुज्ञप्त थोक बाजार तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा (अनु0-1) के अनुज्ञप्त थोक बाजार से तिमाही आधार पर देशी मदिरा या भारत में बनी विदेशी मदिरा का सम्पूर्ण वार्षिक कोटा उठाने के लिए बाध्य होगा। कोटा को उठाने का अर्थ होगा देशी मदिरा (अनु0-13) के अनुज्ञप्त थोक बाजार तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा (अनु0-1) के अनुज्ञप्त थोक बाजार से मदिरा का भौतिक रूप से उठाना। देशी मदिरा तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा का सम्पूर्ण कोटा उठाना अनुज्ञप्तिधारी के लिए नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार बाध्यकर होगा :-

संचित उत्थापन	तिमाही	मासवार	
वार्षिक मूल कोटे का 25 प्रतिशत	अप्रैल मई जून	9 प्रतिशत 8 प्रतिशत 8 प्रतिशत	25 प्रतिशत
वार्षिक मूल कोटे का 45 प्रतिशत	जुलाई अगस्त सितम्बर	7 प्रतिशत 7 प्रतिशत 6 प्रतिशत	20 प्रतिशत
वार्षिक मूल कोटे का 75 प्रतिशत	अक्टूबर नवम्बर दिसम्बर	10 प्रतिशत 10 प्रतिशत 10 प्रतिशत	30 प्रतिशत
वार्षिक मूल कोटे का 100 प्रतिशत	जनवरी फरवरी मार्च	9 प्रतिशत 8 प्रतिशत 8 प्रतिशत	25 प्रतिशत

अनुज्ञप्तिधारी को तिमाही आधार पर अपने देशी शराब के अधिकतम 10 प्रतिशत कोटा को भारत में निर्मित विदेशी मदिरा में बदलने की स्वतन्त्रता होगी।

तिमाही कोटे को उठाने के सम्बन्ध में उपबन्ध के अननुपालन में देशी मदिरा तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा की अपूर्ण मात्रा के लिए क्रमशः 40/- रुपये तथा 80/- रुपये प्रति प्रूफ लीटर की दर से शास्ति लगाई जाएगी।

अनुज्ञप्तिधारी को अपना कोटा देसी मदिरा के लिए ₹6 प्रति प्रूफ लीटर तथा भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के लिए ₹12 प्रति प्रूफ लीटर अन्तरण फीस अदा करने के बाद अन्तरण किया जाएगा जो कोटा अन्तरण के लिए अनुज्ञप्तिधारी के ऐसे अनुरोध पर अन्तरण करने वाले लाईसेंसी के द्वारा अदा की जाएगी”।

- (vii) उप-नियम (19) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(19) कोई भी व्यक्ति जिसको खुदरा मदिरा बाजार के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है, ऐसे परिसरों में उसे स्थापित नहीं करेगा जो मान्यताप्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/मुख्य बस अड्डे तथा पूजा के स्थान के मुख्य दरवाजे से कम से कम 150 मीटर की दूरी पर स्थित हो। तथापि आबकारी आयुक्त उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त की सिफारिश पर 150 मीटर से 75 मीटर के लिए खुदरा मदिरा बाजार की अवस्थिति के लिए ऐसी दूरी में छूट दे सकता है। इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्रों में, खुदरा मदिरा बाजार मार्केट स्थानों में अवस्थित होंगे। तथापि, यह उपबन्ध ऐसे मामले में लागू नहीं होगा जहां नया मान्यताप्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/मुख्य बस अड्डा या पूजा का स्थान वर्ष 2018-19 में ठेके की स्थापना के पश्चातवर्ती वर्ष की चालू रहने के दौरान 150 मीटर के दूरी में आते हैं।”।

- (viii) उप-नियम (24) से (27) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

“(24) अनुज्ञप्तिधारी शहरी क्षेत्र के पॉश मार्केट या शॉपिंग माल में अपने संयुक्त ठेकों में से एक या इससे अधिक ठेकों को मॉर्डन शॉप में परिवर्तित करेगा, जहाँ वह केवल भारत में निर्मित विदेशी शराब को बेचने का इरादा रखता है। इस प्रयोजन के लिए, शहरी क्षेत्रों के पॉश मार्केट या शॉपिंग माल में कुछ खुदरा दुकानों को आबंटित मॉर्डन शॉप के रूप में पहचाना जाएगा। आधुनिक दुकानों को क्षेत्र के ग्राहक-गण तथा सम्भावना को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा पहचाना जाएगा। आधुनिक दुकानों में भारतीय विदेशी मदिरा (बोआईओ) के लिए



पृथक वर्ग होगा। आधुनिक दुकानें किसी अतिरिक्त आबकारी शुल्क के बिना अर्थात् आबकारी शुल्क की दर पर अपने मूल कोटे के 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त कोटे को उठाने के लिए हकदार होगा:

परन्तु मशीन द्वारा तैयार बिल का प्रोविजन सभी खुदरा लाईसैंसियों के लिए बिल जारी करने के लिए आवश्यक होगा। इस प्रोविजन की उल्लंघना की दशा में, सम्बन्धित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आ0) के जाँच करने के बाद प्रत्येक केस पर ₹500 की शास्ति लाईसैंसी पर लगायी जायेगी। आगे उपबन्धित किया जाता है कि यदि ₹15 करोड़ के बराबर या अधिक की अनुज्ञप्ति फीस वाले शहरी क्षेत्र का कोई अनु0-2 अनुज्ञप्तिधारी ठेके के आबंटन के बाद आधुनिक दुकान में अपने ठेके को बदलना चाहता है, तो उसे विभाग के अनुमोदन से ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है। ऐसे आवेदनों को जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी), उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (विक्रय कर) तथा दो वरिष्ठतम आबकारी तथा कराधान अधिकारियों से मिलकर बनी (समिति) द्वारा परीक्षित किया जाएगा तथा अनुमोदन के लिए विचार जाएगा।

(25) खुदरा ठेकों के जोन के प्रत्येक सफल आबंटिती के लिए जोन के ठेकों की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के 21 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करानी अपेक्षित होगी, जिसमें से अनुज्ञप्ति फीस का 5 प्रतिशत ई-बोली के मुल्यांकन के दिन को; अनुज्ञप्ति फीस का 5 प्रतिशत आबंटन के दिन के सात दिन के भीतर या 31 मार्च को या से पूर्व, जो भी पहले हो, जमा करवाई जाएगी; तथा अनुज्ञप्ति फीस के 11 प्रतिशत के बराबर शेष प्रतिभूति 7 अप्रैल, 2018 तक जमा कराई जाएगी। उसके बोली धन का 82 प्रतिशत उसके बोली धन के 8.2 प्रतिशत की दस बराबर मासिक किस्तों में उस द्वारा भुगतानयोग्य होगा; जो कि ठेके/समूह ठेकों के उसके प्रचालन के प्रारम्भ के मास से शुरू होने वाले प्रत्येक मास की 20 तारीख तक तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती मास तक भुगतान योग्य होगा। भुगतान मासिक किस्तों के रूप में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 82 प्रतिशत की सम्पूर्ण राशि के भुगतान करने तक निरन्तर जारी रहेगा। उसकी प्रतिभूति का भाग, उसके बोली धन के 18 प्रतिशत के बराबर, उसके बोली धन के 82 प्रतिशत तक की राशि की किस्तों के भुगतान के बाद उसकी अनुज्ञप्ति फीस की ओर अन्त में समायोजित किया जायेगा। समायोजन उसकी बोली धन के 9 प्रतिशत की प्रत्येक, दो बराबर किस्तों में दो मास की अवधि में किया जाएगा।

(26) उसके बोली धन के 3 प्रतिशत के बराबर शेष प्रतिभूति 15 अप्रैल, 2019 तक उसकी ओर बकाया था असंदत पाई गई किसी राशि को समायोजन करने के बाद वापस की जाएगी। यह राशि जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा वापस की जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई ब्याज प्रतिभूति राशि पर भुगतानयोग्य नहीं होगा। यदि आबंटिती/अनुज्ञप्तिधारी विहित समय में प्रतिभूति का सम्पूर्ण भुगतान करने में असफल रहता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति स्वतः रद्द हो जाएगी तथा जमा प्रतिभूति, यदि कोई हो, जब्त हो जाएगी। किन्हीं दस किस्तों के भुगतान के लिए विहित समय का पालन करने में असफलता की दशा में, देरी से किए गए भुगतान पर ब्याज 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से भुगतान की तिथि तक चूक के मास के प्रथम दिन से प्रभारित किया जाएगा।

(27) जोन के ठेकों की दशा में जो वित्तीय वर्ष के चालू रहने के दौरान आबंटित/पुनः आबंटित किए गए हैं, बोली धन के 10 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति आबंटन के दिन जमा की जाएगी तथा बोली धन के 11 प्रतिशत के बराबर शेष प्रतिभूति आबंटन के तिथि के दस दिन के भीतर जमा की जाएगी। ठेकों का जोन आबंटन/पुनः आबंटन की आगामी तिथि से प्रचालन में आएगा। मास जिसमें आबंटन/पुनः आबंटन किया गया है के लिए अनुज्ञप्ति फीस, उस मास के शेष दिनों के अनुपात में, मास की समाप्ति तक भुगतानयोग्य होगी। अनुज्ञप्ति फीस के 82 प्रतिशत में से शेष राशि बराबर मासिक किस्तों में जनवरी तक भुगतानयोग्य होगी, उसके बाद, उसकी प्रतिभूति अन्य आबंटनों के मामले में समायोजित की जाएगी। यदि आबंटन या पुनः आबंटन दिसम्बर, 2018 के बाद किया जाता है तो उसके बोली धन का 82 प्रतिशत मास की अन्तिम तिथि तक वसूल किया जाएगा जिसमें आबंटन/पुनः आबंटन किया गया है। आबंटन/पुनः आबंटन के मास के लिए किस्त को, पूर्ण मास के रूप में संगणित समझा जाएगा।

यदि आबंटन/पुनः आबंटन 20 से पूर्व किया जाता है तो भुगतान की तिथि 20 होगी या यदि आबंटन 20 को या बाद में किया जाता है, तो भुगतान मास के अन्तिम दिन को होगा। कोई भी ब्याज प्रतिभूति राशि पर भुगतानयोग्य नहीं होगा।”।

6. उक्त नियमों में, नियम 37 में, उप नियम (32) में, खण्ड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(iv) देशी मदिरा के लिए ₹ 6.00 प्रति पूफ लीटर, भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के सभी ब्रांडो के लिए ₹12.00 प्रति पूफ लीटर तथा बीयर के लिए ₹10 प्रति बल्क लीटर की दर से स्टॉक अन्तरण फीस उदगृहीत की जाएगी,

परन्तु कि कलैक्टर(आबकारी) के अनुमोदन के बाद, मौजूदा लाईसैंसी को, केवल थौक लाईसैंसी की स्थिति में, पिछले वर्ष के लाईसैंसी के बचे हुए स्टॉक को अंतर-जिला हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाएगी।

ऐसे मामलों में स्टॉक ट्रांसफर फीस देशी मदिरा के लिए ₹9.00 प्रति प्रूफ लीटर, भारत में बनी विदेशी मदिरा के लिए ₹15.00 प्रति प्रूफ लीटर तथा बीयर के लिए ₹12.00 होगी।

परन्तु यह और कि चालू वर्ष के दौरान थौक लाईसेंसी के द्वारा छोड़े हुए स्टॉक को कलैक्टर (आबकारी) के द्वारा उसी जिले के अन्य लाईसेंसी या दूसरे जिले के लाईसेंसी को भी हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामलों में स्टॉक ट्रांसफर फीस देशी मदिरा के लिए ₹9.00 प्रति प्रूफ लीटर, भारत में बनी विदेशी मदिरा के सभी ब्रांडों के लिए ₹15.00 प्रति प्रूफ लीटर तथा बीयर के लिए ₹12.00 होगी।

**टिप्पण.—** जहाँ वर्ष 2018-2019 के लिए आबकारी नीति में किसी भी प्रकार की मदिरा के आबकारी शुल्क के रेट में वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2017-2018 के लिए आबकारी शुल्क की दर से अधिक है, दिनांक 01-04-2018 को बचे हुए स्टॉक पर अन्तर आबकारी शुल्क स्टॉक ट्रांसफर फीस के अतिरिक्त, यदि कोई हो, देय होगी।”।

7. उक्त नियमों में, नियम 37 में, उप नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा,—

“(2) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति में विहित परिसर के सिवाय (जिन्हें इसमें, इसके बाद उक्त अनुज्ञप्ति परिसर कहा गया है) पर कोई ऐसा कारोबार या अनुज्ञप्ति के अधीन मान्य शराब के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की शराब नहीं रखेगा। कलक्टर केवल विशेष मामलों में, जहाँ अनुज्ञप्त स्थान पर अधिक मात्रा में शराब रखने की जगह न हो, आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1) की धारा 24 की उप-धारा (3) के अधीन अनुज्ञप्त स्थान के अतिरिक्त खुदरा बिक्री से अधिक मात्रा में शराब किसी अन्य स्थान पर रखने हेतु 5,00,000 रुपये अतिरिक्त वार्षिक फीस की अदायगी पर अनुमति प्रदान करेगा बशर्त कि उक्त परिवार की दूरी अनुज्ञप्त ठेके से 100 मीटर से कम होगी। कलक्टर ऐसी अनुमति देने से पूर्व स्वयं की सन्तुष्टि करेगा कि प्रस्तावित स्थान पूर्ण रूप से सुरक्षित है और यह आम जनता की पहुँच से दूर है।

8. उक्त नियमों में, नियम 38 में, उप नियम (16क) में,—

(i) खण्ड (कक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

(कक) मदिरा बेचने के लिए किसी दुकान को कोई लाईसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा अर्थात्—

(i) राष्ट्रीय राज मार्ग या राज्य राज मार्ग से दिखाई देने वाला;

(ii) राष्ट्रीय राज मार्ग या राज्य राज मार्ग से स्पष्ट तौर पर दिखाई देने वाला; तथा

(iii) राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग या ऐसे राज मार्गों के साथ लगने वाली सर्विस लेन के बाहरी किनारे से 500 मीटर की दूरी पर अवस्थित होंगे;

परन्तु कि उपरोक्त प्रतिबन्ध नगरपालिका क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर स्थित शराब के ठेकों पर लागू नहीं होगा।

मदिरा ठेके जो राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों या ऐसे राजमार्गों के साथ-साथ चलने वाली सर्विस लेनों पर स्थित नहीं है, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) या किसी अन्य लागू विधि के उपबन्धों का अनुपालन करेंगे।

**टिप्पण.—** उपरोक्त नियत निबन्धनों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए सम्बद्ध जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आ0) की जिम्मेवारी होगी।”।

(ii) खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(छ) (क) उप-ठेका खोलने के लिए, अनुज्ञप्तिधारी को नीचे वर्णित पैरा (ड.) के अनुसार के सिवाय ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति उप-ठेके ₹1,50,000/-की नियत वार्षिक फीस के भुगतान पर प्ररूप अनु0-14क, अनु0-2/एसवी में अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी। शहरी क्षेत्रों में उप-ठेके प्रत्येक उप-ठेके लिए ₹15,00,000 की नियत लाईसेंस फीस अदा करने पर अनुज्ञात किया जायेगा। उप-ठेके ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में जोन के कमाण्ड एरिया में अनुज्ञात किए जायेंगे। उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) की पूर्वानुमति के अधधीन शहरी क्षेत्रों में दो उप ठेके तक ही अनुज्ञात किए जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में उप ठेकों के लिए नीचे वर्णित पैरा (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) के अनुसार उपबन्ध लागू होंगे;

(ख) उप-ठेके 1000 (2011 की जनगणना के अनुसार) से अधिक की जनसंख्या की प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे;

(ग) 1000 (2011 की जनगणना के अनुसार) से कम की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत के लिए उप-ठेके, उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) की सिफारिश पर कलक्टर (आबकारी) द्वारा ग्राम पंचायत की सहमति से अनुज्ञात किए जाएंगे;

- (घ) उप-ठेका उस ग्राम पंचायत में अनुज्ञात किया जाएगा जहां मुख्य ठेका अवस्थित हैं, यदि ऐसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 5000 (2011 की जनगणना के अनुसार) से अधिक है; तथा
- (ड.) 2000 (2011 की जनगणना के अनुसार) से कम जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत में अवस्थित उप-ठेके के लिए फीस ₹ 75,000/- प्रति उप-ठेका होगी।”।

आशिमा बराड,  
आबकारी तथा कराधान आयुक्त,  
हरियाणा।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

**Notification**

The 28th March, 2018

**No. 35/X-I/P.A. 1/1914/S.59/2018.-** In exercise of the powers conferred by section 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914) and with reference to the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 67/X-I/P.A.1/1914/S.9/2017, dated the 4th August, 2017, I, Ashima Brar, Excise Commissioner, Haryana exercising the powers of Financial Commissioner hereby make the following rules further to amend the Haryana Liquor License Rules, 1970, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Liquor License (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force with effect from the 1st April, 2018.

2. In the Haryana Liquor License Rules, 1970 (hereinafter called the said rules), in rule 24,-

(i) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

“(i) for a license in form L-1,-

(a) for revenue districts of Gurugram and Faridabad ₹ 1,60,00,000

(b) All other districts in the State Except Gurugram and Faridabad ₹ 1,30,00,000

Provided that no such license shall be issued unless a refundable security of thirty lakh rupees is deposited which shall be liable to be forfeited or adjusted for any amount or penalty due under the Act.”;

(ii) for clause (i-bb), the following clauses shall be substituted, namely:-

“(i-bb) for licenses in form L-4/L-5:-

(a) L-4/L-5 licenses granted to the hotels ₹ 40,00,000  
of 5 Star grading and above:

Provided that L-4/L-5 licensees shall also be granted in emerging residential townships and such places where Haryana State Industrial Development Corporation has developed Industrial Model Townships and Theme/Specialized Parks like Industrial Model Townships, Manesar, Industrial Model Townships, Bawal, Industrial Model Townships, Rohtak, Industrial Town Park Manesar, Technology Park, Panchkula:

Provided further that such licensees shall be allowed one main bar and three additional points, alongwith room service (L-3), without any further fee. Such licensee shall further be allowed to operate the main bar round the clock. By virtue of having L-3 license, these hotels are allowed to keep liquor in the refrigerators kept in the hotels rooms along with other food articles and beverages. L-4/L-5 licensee bars can remain open upto 12.00 hours (Midnight). The timings of bars can be extended by one hour on payment of additional annual fee of Rs. 10 Lakh. Sale of liquor including imported foreign liquor made through L-4/ L-5 outlets (bars) shall attract VAT @ 18 % + surcharge @ Rs. 5% on VAT.

(b) Hotels having grading of 4 Star: ₹ 33,00,000

Provided that such licensee shall be allowed one main bar and two additional points, alongwith room service (L-3), without any further fee. Such licensee shall further be allowed to operate the main bar round the clock. By virtue of having L-3 license, these hotels are allowed to

keep liquor in the refrigerators kept in the hotels rooms along with other food articles and beverages.

Provided further that L-4/L-5 license shall also be granted provisionally to a Hotel located anywhere in the State subject to the condition that the applicant shall procure star classification of 4 star and above from the Ministry of Tourism, Government of India within the financial year of grant, failing which the provisional license shall not be renewed subsequently. The licensee shall apply for the star rating within one month of obtaining the L-4/L-5 license:

- (c) Hotels having grading of 3 Star: ₹ 18,00,000

Provided that such licensee shall be allowed one main bar, alongwith one additional point and room service (L-3), without any further fee. By virtue of having L-3 license, these hotels are allowed to keep liquor in the refrigerators kept in the hotels rooms along with other food articles and beverages.

Provided further that such licensee of category (a), (b) and (c) mentioned above shall also be allowed to serve liquor in functions, parties, events and meetings, held in up to three (03) of their identified and approved halls including banquet halls and ground floor lawns, sourced from the main bar, on payment of a one - time fee equal to 50% of his annual license fee.

The L-4/L-5 and L-12C licensees shall be allowed to procure Imported Foreign Liquor (BIO) directly from Custom Bonded Warehouses, only from outside the State with the permission of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the district concerned who shall ensure disposal of such a request within a week. The bar licensees are also allowed to take their supplies of Imported Foreign Liquor (BIO) from L-1BF in the State. Further, the bar licensees procuring Imported Foreign Liquor (BIO) from any other source other than L-1BF shall pay a permit fee at the rate of ₹ 60.00 per Proof Litre in case of Scotch, Whisky, Rum, Vodka, Gin and Brandy and a permit fee of ₹ 20/- per bulk litre in case of wine, liquor, beer and cider. In addition to the permit fee, an assessment fee will be levied on Indian Made Foreign Liquor (BIO) when imported directly from outside the State. The assessment fee shall be levied at the hands of bar licensees at the rate of ₹ 300.00 per Bulk Litre on beer, wine, Liqueur and cider for scotch, whisky, rum, vodka, gin, brandy etc. shall be ₹ 1200/- per proof litre:

Provided that a refundable security of ₹5,00,000 Lacs shall be taken from the L-4/L-5 licensees in addition to the license fee.”;

- (d) For a license in form L-4/L-5, for clause (d) and (e), the following clauses shall be substituted namely:-

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| (d) For Bar(s) operated by Haryana Tourism Corporation.                                    | A composite fee of ₹ 2,00, 00,000 |
| (e) Bars operated by Haryana Urban Development Authority in their Gymkhana and Golf Clubs: | A composite fee of ₹ 1,00,00,000  |

Provided that a composite security of ₹6,00,000 Lacs shall be taken from Haryana Tourism Corporation and Haryana Urban Development Authority in addition to the composite license fee.

- (iii) (a) in clause (ii), for the figure and sign “50,00,000”, the figure and sign “60,00,000” shall be substituted;
- (b) in clause (ii-a), for the figure and sign “40,00,000”, the figure and sign “50,00,000” shall be substituted;
- (c) in clause (ii-b), for the figure and sign “75,00,000”, the figure and sign “80,00,000” shall be substituted;
- (d) in clause (ii-b), for heading “Franchise Fee” and entries thereunder, the following heading and entries thereunder shall be substituted, namely:-

“Franchise Fee

Indian Made Foreign Spirit	20.00 per proof litre
Beer	14.00 per bulk litre”;

- (iv) after clause (ii-b), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

“Provided that a letter of intent shall be obtained by the applicant for setting up a bottling plant in the State of Haryana. The letter of intent shall be issued with certain terms and conditions with a specified period of validity. It shall be issued with the permission of the Government and a fee per annum for grant and renewal of letter of intent shall be Rs. 30 lakh. Fee for revalidation of letter of intent for the first extension of one year shall be at the rate equal to the fee for grant of letter of intent and for each subsequent extension of one year, the revalidation fee shall be 125% by the previous year's fee. The fee for revalidation of letter of intent where previously no fee for letter of intent or its revalidation was charged shall be charged @ ₹ 30 lakh and subsequent revalidation shall be 125% of the previous year's fee”.

- (v) for clause (ii-c), the following clause shall be substituted, namely: -

“(ii-c) The bottling fee on Indian Made Foreign Spirit shall be levied as under: -

- |     |  |                           |
|-----|--|---------------------------|
| (a) | for D-2 licenses bottling their own brands   | ₹ 11.00/- per Proof Litre |
| (b) | for bottling plants bottling their own brands  | ₹ 18.00/-per Proof Litre  |
| (c) | for bottling of brands not covered in (a) and (b) above and where no franchise fee is levied | ₹ 20.00/- per Proof Litre |
| (d) | for bottling of beer by the brewers  | ₹ 6.00/- per Bulk Litre   |

Provided that bottling fee shall be leviable on liquor for export as well as on liquor on local consumption, if no franchise fee is levied.

- (vi) in clause (iv), for the existing proviso at the end, the following proviso shall be substituted, namely: -

“Provided that a license in form L-12A may be granted by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) to an individual at private place beyond possession limit for a day on payment of ₹500 per day function.

The commercial places like banquet halls, farm houses, community centres, dharamshalas holding functions, get-togethers shall have to be registered with the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the District on payment of a registration fee Rs. 50,000/- per annum. The fee structure in such cases shall be as under:-

- |     |  |                              |
|-----|--|------------------------------|
| (a) | for persons serving liquor at commercial places registered with Excise department.     | ₹5,000 per day per function  |
| (b) | for persons serving liquor at commercial places not registered with Excise department. | ₹10,000 per day per function |

The commercial venues not registered with the department shall not be issued more than 5 licenses per month. The application for grant of L-12A license at all the commercial venues shall mention the details of caterer i.e. name and style, GSTIN, the approximate number of guests and the quantity of liquor.”.

- (vii) for clause (iv-b), the following clauses shall be substituted, namely: -

“(iv-b) for a license in form L-12C,-

- |     |  |                |
|-----|--|----------------|
| (a) | for revenue district Gurugram                                  | ₹ 15,00,000/-  |
| (b) | for district Faridabad   | ₹ 12,00,000/-  |
| (c) | All other district in the State except Gurugram and Faridabad: | ₹ 9,00,000/-”. |

Provided that L-12C licenses shall be granted to the Clubs of repute situated in the district headquarter cities, except as provided hereunder, having infrastructure and level of facilities required to meet the parameters and condition prescribed by the District Level Committee constituted for this purpose:

Provided further that a new license in the form of L-12C for residential condominium shall be allowed at district headquarter cities. The main bar shall be equivalent to the L-4/L-5 license while any additional mini club within the condominium shall also get license @ 20% of the license fee of its main bar for each such additional mini club. This will be subject to the condition that only the residents of the condominium or their guests shall be to utilize this facility:

Provided further that in case of L-12C license granted to Sirhind Club, Ambala, the army official shall be allowed to utilize their quota through CSD canteen while the civilian members shall not be entitled for the liquor supplied through CSD canteen:

Provided further that a refundable security of ₹5,00,000 Lacs shall be taken from the L-12C licensees in addition to the license fee.”;

- (viii) for clause (iv-c) and entries thereagainst the following clauses and entries thereagainst shall be substituted namely:-

“(iv-c) for a license in form L-12CC,-

- |   |               |
|---|---------------|
| (a) Golf Club with the capacity<br>Up to 9 holes (with 2 sale points).  | ₹ 40,00,000/- |
| (b) Golf Club with the capacity<br>Up to 18 holes (with 3 sale points). | ₹ 50,00,000/- |

Provided that license to serve liquor shall only be granted to Golf Clubs having facilities of 9 holes or more and they shall not be permitted as an additional point attached to any hotel or any type of bar license. The L-12CC Club bar licensee can remain open up to 12:00 hours (midnight). The timings of bars can be extended by one hour on payment of additional annual fee of ₹ 10 lac.

**Note 1.** — Any additional point above the points already allowed, shall be allowed on payment of a fee equal to 20 % of the annual license fee for each such point and maximum number of three additional points per license shall be allowed.

**Note 2.**— In case of bars operated by Haryana Tourism and Haryana Urban Development Authority in their Gymkhana and Golf Clubs. They shall be allowed additional point on payment of a fee equal to ₹ 1 lakh for each such point.

Provided that a refundable security of ₹5,00,000 Lacs shall be taken from the L-12CC Club bar licensees in addition to the license fee.”;

- (ix) in clause (v), for clause (i) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely :-

“(v) (i) The annual license fee for the wholesale outlets of country liquor (L-13) shall be ₹ 30.00 lakh per outlet in the district. The licensee shall be required to deposit a refundable security amount of ₹ 10.00 lakh per L-13 outlet in the district.

- (x) for clause (i-c) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(i-c) for a license in form L-1AB ₹ 55,00,000;”

- (xi) for clause (i-cc) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(i-cc) for a license in form L-1AB-1 ₹ 30,00,000;”

- (xii) for clause (i-e) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(i-e) for a license in form L-1B ₹ 35,00,000;”

- (xiii) for clause (i-ee) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(i-ee) (a) for a license in form L-1B1 to a brewer ₹ 35,00,000;”

(b) for a license in form L-1B1 to wine manufacture ₹ 25,00,000;”

- (xiv) for clause (i-eee) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(i-eee) for a license in form L-1B1-A ₹ 45,00,000;”

(Ready to drink beverages)

- (xv) for clause (i-eeee), the following clause shall be substituted, namely : -

“(i-eeee) For a license in form L-1BF. –

- (a) Reserve prise shall be ₹ 62,50,00,000/-

- (b) The license in form L-1BF shall be allotted through e-bidding to the highest bidder
- (c) There shall be only one L-1BF license in the State
- (d) L-1BF licensee shall be allowed to open maximum of three outlets/branches, in addition to the main outlet, anywhere in the State for which a fixed fee @ 2% of the license fee of L-1BF per outlet/branch shall be levied.
- (e) In case no eligible bid equal to or above the reserve price is received for the lone L-1BF license, the same shall be allotted exclusively to a Government owned entity on the terms and conditions as decided by the Government. The permit and brand label fee shall be levied as under to procure Stock of liquor by the L-1BF licensee

**PERMIT FEE**

- (a) Scotch, Whisky, Rum, Vodka, Gin, Brandy etc. ₹ 75 per Proof litre
- (b) Wine, Liquor, Beer and Cider ₹ 30 per Bulk litre

**Brand Level Fee**

- (a) Scotch/Whisky, ₹ 70,000 per brand
- (b) Beer ₹ 60,000 per brand
- (c) Rum/Vodka/Wine ₹ 35,000 per brand
- (d) Gin/Brandy Cider/Champagne/Liquor ₹ 25,000 per brand.”;

(xvi) for clause (i-g), the following clause shall be substituted, namely :-

“(i-g) For a license in form L-1-C	Annual fee at the rates given below against each :-
(I) Whisky/Scotch	₹ 95,000 per brand
(II) Beer	₹ 75,000 per brand
(III) Rum	₹ 55,000 per brand
(IV) Gin/Vodka	₹ 40,000 per brand
(V) Wine/Brandy/Cider/Champagne	₹ 25,000 per brand
(VI) Vodka/Brandy/Cider/Wine and Champagne for supply to CSD	₹ 10,000 per brand
(VII) Country Liquor	₹ 95,000 per brand
(VIII) Ready to Drink Beverages (RTB)	₹ 85,000 per brand
(IX) Brand label fee for exports out of State (for all types of brands):	₹ 60,000 per brand

Provided that bottling fee shall be leviable on liquor for export as well as on liquor on local consumption, if no franchise fee is levied.

3. In the said rules, in rule 27-A,-

(i) in sub-rule (1), for clauses (iii), (iv) and (v) the following clauses shall be substituted, namely:-

- “(iii) (a) The fee for license in form L-10B obtained by L-2 licensee Located in shopping malls. ₹10,00,000
- (b) The fee for license in form L-10B located in departmental sotres in the shopping malls. ₹20,00,000
- (iv) for a license in form L-10C ₹12,00,000
- (v) for a license in form L-10E ₹8,00,000

4. In the said rules, in rule 31-A, for the figure “300”, the figure “325” shall be substituted.

5. In the said rules, in rule 36-A-,

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) The allotment of retail outlets of country liquor and Indian Made Foreign Liquor shall be grouped into Zones in urban and rural areas through e-tendering. The Command area of a Zone shall be the geographically area specified for the Zone in the Excise Arrangements. The Command area for a

Zone shall include both urban and rural areas. The licensee shall have the flexibility to decide the type of vend i.e. Country Liquor only or Indian Made Foreign Liquor only or both Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor. The overall limit shall be of six (06) retail vends, and shall locate his vends at any place within the command area of the Zone with prior approval of the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the district. The licensee shall also decide the proportionate quota for each individual vend for Country Liquor/ Indian Made Foreign Liquor as the case may be. The process of allotment shall be conducted by a committee consisting of the Deputy Commissioner with Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise), Deputy Excise and Taxation Commissioner (Sales Tax) of the respective districts as its members in the presence of the participants who wish to be present on the date of evaluation of e-bids to be published by the department in the newspapers. The allotment of Zone of vends shall be done by way of inviting e-bids. The Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) shall upload the Geographic Information System coordinates of all L-2, L-14A vends, sub-vends and anumat-kaksh located in his district:

Provided that in case of cancellation of a license, the process of re-allotment shall be initiated by inviting e-bids through advertisement immediately. The reserve price for re-allotment shall be computed proportionately for the remaining period for which the Zone of vends is to be re-allotted using the original license fee. In case no bid is received, the reserve price shall be further reduced by 10 % of the above mentioned original reserve price or Rs. 50 lac, whichever is lower and the process of inviting e-bids shall be repeated till the Zone of vends is re-allotted. This re-allotment shall be done at the risk and cost of original licensee.”.

- (ii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) The detailed procedure regarding invitation of e-bids will be finalized by the Excise and Taxation Commissioner (Financial Commissioner) which shall be displayed on the web-site of the department [www.haryanatax.gov.in](http://www.haryanatax.gov.in) At the time of applying for registration for participation in the bid, submission of Aadhar Number of the applicant(s) shall be mandatory. To avoid any legal complications, in case no decision of Excise and Taxation Commissioner (FC) is conveyed within the stipulated period of ten days, the allotment shall be deemed to have been approved by the Excise and Taxation Commissioner (FC)”

- (iii) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(5) The bidder shall have to deposit a participation fee of ₹ 75,000 for each Zone. The participation fee is non refundable and non adjustable. The participation fee shall be deposited in the Office of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) concerned either in cash or by demand draft in favour of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) .”.

- (iv) In sub-rule (12), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

“(12) All successful allottees, before the start of operation of vends in his zone, shall be required to file an affidavit and a solvency certificate. Affidavit shall be on a non-judicial stamp paper of the value of Rs. 3/- in the format prescribed in the form. The affidavit will be to the effect that he has not been convicted of any non-bailable offence by a criminal court or of any offence punishable under the Punjab Excise Act or the Opium Act, the East Punjab Opium Smoking Act, 1948, the East Punjab Molasses (Control) Act, 1948, the Indian Power Alcohol Act, 1948 applicable to Haryana or the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985. The affidavit will also be to the effect that he is not a defaulter and has paid all past dues of excise revenue in Haryana. The failure to furnish the affidavit or solvency certificate prescribed herein or furnishing false affidavit shall be sufficient ground for cancellation of license, which shall be reallocated at his cost and risk:

Provided that all successful allottee shall submit certain documents namely proof of identity having his/her photograph like voter ID card, passport, ration card, driving license, Aadhar Card (UID) etc., and surety in the form of M-75. All the documents have to be duly attested by a Notary Public or Gazetted Officer and duly stamped with his name and designation. The documents shall be submitted before the start of his/her business. The successful allottee shall provide a photocopy of his PAN Card issued by the Income Tax Department alongwith other documents.”.

- (v) In sub-rule (15), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

“(15) The Licenses shall be granted by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the district on behalf of the Collector after the approval of Excise and Taxation Commissioner (Financial Commissioner), Haryana. Before granting the licenses, the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) shall ensure that the essential documents are submitted.



- (vi) In sub-rule (17), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

“(17) The licensee to whom a retail liquor outlet of country liquor (L-14A) or Indian Made Foreign Liquor (L-2) is allotted, shall be bound to lift its entire annual quota of Country Liquor or Indian Made Foreign Liquor on quarterly basis from the licensed wholesale outlet of Country Liquor (L-13) and licensed wholesale outlet of Indian Made Foreign Liquor (L-1) located at every district headquarter in the State. The lifting of quota shall mean physical lifting of liquor from the licensed wholesale outlet of Country Liquor (L-13) and licensed wholesale outlet of Indian Made Foreign Liquor (L-1). It shall be obligatory for a licensee to lift entire basic quota of Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor to his/ her Zone of vends as per the schedule below:-

Cumulative lifting	Quarter	Monthwise	
25% of annual basic quota	April May June	9% 8% 8%	25%
45% of annual basic quota	July August September	7% 7% 6%	20%
75% of annual basic quota	October November December	10% 10% 10%	30%
100% of annual basic quota	January February March	9% 8% 8%	25%

The licensee shall have the freedom to convert maximum 10% of his Country Liquor quota to Indian Made Foreign Liquor on quarterly basis.

Non compliance of the provision regarding lifting of quarterly quota shall attract penalty at the rate of Rs. 40/- and Rs. 80/- per proof litre of Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor respectively for the deficient quantity.

The licensee shall also be allowed to transfer his quota after paying the transfer fee of ₹ 6.00 per Proof Litre for Country Liquor and ₹ 12.00 per Proof Litre for Indian made foreign liquor which shall be payable by the transferor licensee at the time of making such request for transfer of quota”.

- (vii) for sub-rule (19), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(19) No person to whom a license for retail liquor outlet is granted shall establish the same on such premises as is situated at a distance of less than 150 meters from the main gate of a recognized school/ college/main bus stand and a place of worship. However, Excise Commissioner can relax such distance for the location of retail liquor outlet for 150 meters to 75 meters on the recommendations of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise). Further, in urban areas, the retail liquor outlets shall be located in the market places. However, this provision shall not apply in such cases where a new recognized school/college/main bus stand or a place of worship comes up with a distance of 150 meters during the currency of the year subsequent to the establishment of vend in the year 2018-2019.”.

- (viii) for sub-rule (24) to (27), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

“(24) The licensee shall convert one or more of his composite vends to Modern Shop(s) in posh market or shopping mall of the urban area, where he intends to sell Indian Made Foreign Liquor only. For this purpose, some of the retail outlets in the posh markets or Shopping Malls of the Urban Areas shall be identified to be allotted as Modern shops. The Modern Shops shall be identified by the department, keeping in view the clientele and potential of the area. The modern shops shall have a separate section for Indian Foreign Liquor (BIO). The modern shops shall be entitled to lift an additional quota up to 10% of his basic quota without any additional excise duty i.e. at the rate of excise duty as applicable to basic quota:

Provided that the provision of machine generated invoices (POS) shall be mandatory for all the retail licensees to issue an invoice on sale. In case of violation of this provision, a penalty of ₹ 500 per incident shall be imposed on the licensee, after enquiry by the Deputy Excise & Taxation Commissioner

(Excise) concerned. It is provided further that if any retail Licensee in urban areas having license fee of his zone equal to or above ₹ 15 crore, wants to convert his vend into a Modern shop after allotment of vends, he may be allowed to do so with the approval of the Department. Such applications may be examined and considered for approval by a committee comprising of the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise), Deputy Excise and Taxation Commissioner (Sales Tax) and two senior most Excise and Taxation Officers of the district.”

“(25) Every successful allottee of retail Zone of vends shall be required to deposit a security amount equal to 21% of the annual license fee of the Zone of vends, out of which, 5% of the license fee shall be deposited on the day of evaluation of e-bids; 5% of the license fee within seven days of the allotment on or before 31st March, whichever is earlier; and the remaining security equal to 11% of the license fee shall be deposited by 7th of April, 2018. The 82% of his bid money shall be payable by him in ten equal monthly installments equal to 8.2% of his bid money; each payable by 20th of each month starting from the month of commencement of his operation of vends in their Zones, and every subsequent month. The payment shall continue till full amount of 82% is paid by the licensee by way of monthly installments. A part of his security, equal to 18% of his bid money, shall be adjusted at the end towards his license fee after the payment of installments amounting to 82% of his bid money. The adjustment shall be made over a period of two months in two equal installments; each equal to 9 % of his bid money.

“(26) The balance security equal to 3 % of his bid money shall be refunded after adjusting any amount found outstanding or unpaid towards him by the 15th April, 2019. This amount shall be refunded by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the District. No interest of any kind shall be payable on the security amount. If an allottee/ licensee fails to make the full payment of security in the prescribed time, his license shall be cancelled automatically and security deposited, if any, forfeited. In case of failure to adhere to the prescribed time for payment of any of the ten installments, interests on late payment shall be charged from the first day of the month of default till the date of payment @ 18% per annum.

“(27) In case of Zone of vends which are allotted/re-allotted during the currency of the financial year, the security equal to 10% of bid money shall be deposited on the day of allotment and remaining security equal to 11% of bid money shall be deposited within ten days of the date of allotment. The Zone of vends shall come into operation from the day following the date of allotment/re-allotment. The license fee for the month in which the allotment/re-allotment is made shall be payable by the end of the month, in proportion to the remaining days of that month. The remaining amount out of 82% of the license fee shall be payable upto January in equal monthly installments. Thereafter, his security shall be adjusted as in case of other allotments.

In case the allotment or re-allotment takes place after December, 2018, the 82% of his bid money shall be recovered upto the last date of month in which it is allotted/re-allotted. The installment for the month of allotment/re-allotment shall be computed treating it as a full month.

The date of payment for the month of allotment/re-allotment shall be 20th if allotment takes place before 20th or the last day of the month if allotment takes place on or after 20th. No interest shall be payable on the security amount.”

6. In the said rules, in rule 37, in sub-rule (32), for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:-

“(iv) The stock transfer fee shall be levied at the rate ₹6.00 per proof litre for country liquor, ₹12 per proof liter for all brands of Indian Made Foreign Liquor and ₹ 10 for beer per bulk litre.”

Provided further that inter-district transfer of left over stock of the licensee of the pervious year to a current licensee shall be allowed only in case of wholesalers, after approval of the Collector (Excise). The stock transfer fee in such cases shall be ₹ 9.00 per proof litre for country liquor, ₹ 15.00 per proof litre for all brands of Indian Made Foreign Liquor and ₹ 12.00 per bulk litre for beer.

It is further provided that stock surrendered due to determination of wholesale license during the currency of the year shall also be allowed to be transferred to another licensee of the same district or to another licensee of some other district by the Collector (Excise). The stock transfer fee in such cases shall be ₹ 9.00 per proof litre for country liquor, ₹ 15.00 per proof litre for all brands of Indian Made Foreign Liquor and ₹ 12.00 per bulk litre for beer.

**Note.**— Where the rate of excise duty in the Excise Policy for the year 2018-19 have been increased in case of any type of liquor over the rates of excise duty for the years 2017-18, the differential excise duty on the unsold stock as on 01.04.2018 shall be payable, in addition to the stock transfer fee, if any.

7. In the said rules, in rule 37, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) The licensee shall not carry on any business connected with his license or store any liquor to be sold or otherwise dealt with under his license except in the premises specified in his license (hereinafter called the licensed premises). The Collector only in the exceptional cases, where it is impossible and impracticable to carry and store in the licensed premises large consignment of liquors, with previous sanction of Excise Commissioner may grant a permit under sub-section (3) of section 24 of the Punjab Excise Act, 1914, to store a quantity of liquor exceeding the limit of retail sale at a place other than the licensed premises on payment of extra fee of Rs. [5,00,000] per annum and subject to the condition that distance of the said premises from the vend shall be less than 100 meters. Before the grant of the permit, the collector shall satisfy himself that the proposed place is adequately guarded and that there is no means of access to it by the public”.

8. In the said rules, in rule 38, in sub rule (16A),-

(i) for clause (aa) the following clause shall be substituted namely :-

“(aa) No license for sale of liquor shall be granted to a shop that is :

- (i) visible from a National or State Highway;
- (ii) directly accessible from a National or State Highway and
- (iii) situated within a distance of 500 meters of the outer edge of the National or State Highway or of a service lane along the highway:

Provided that above restrictions shall not apply to the liquor vends located within the limits of municipal areas.

The liquor vends which are not located on National/State Highways or the service lanes running along such Highways, shall comply with the provisions of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (41 of 1963) or any other law applicable.

**Note.**— It shall be the responsibility of the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the district concerned to ensure the strict compliance of the above stipulated restrictions.

(ii) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:-

- “(g) (a) For opening a sub-vend, the licensee shall have to obtain a license in form L-14A, L-2/SV on payment of fixed annual fee of ₹ 1,50,000/- per sub-vend in rural areas except as per para (e) mentioned below. Sub-vends in urban areas shall be allowed on the payment of fixed license fee of ₹ 15,00,000/- per sub-vend. Sub-vends shall be allowed within the command area of the Zone for both rural and urban areas. For urban areas, upto two sub-vends per Zone shall be allowed, subject to the prior approval of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise). For sub-vends in rural areas, the provisions shall be applied as per para (b), (c), (d) and (e) mentioned below.
- (b) Sub-vends shall be allowed for each Gram Panchayat with a population more than 1000 (as per 2011 census).
  - (c) Sub-vends for a Gram Panchayat having population less than 1000 (as per 2011 census), shall be allowed with the consent of the Gram Panchayat, by the Collector (Excise), on the recommendation of the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise).
  - (d) A sub-vend shall be allowed in a Gram Panchayat where the main vend is located, if the population of such Gram Panchayat is more than 5000 (as per 2011 census).
  - (e) The fee for a sub vend located in a Gram Panchayat having population less than 2000 (as per 2011 census) shall be ₹75,000 per sub-vend.”.

ASHIMA BRAR,  
Excise and Taxation Commissioner,  
Haryana.